



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940

No. 838]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

गृह मंत्रालय

(महिला सुरक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1140(अ).—बंदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध किंगडम ऑफ स्पेन की सरकार के लिए लागू होंगे। भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ स्पेन के बीच दिनांक 30.05.2017 को हस्ताक्षरित दण्डित व्यक्तियों के अंतरण संबंधी करार का पूरा पाठ नीचे दिया गया है। इस करार का भारत गणराज्य की सरकार द्वारा 03.07.2017 को तथा किंगडम ऑफ स्पेन की सरकार द्वारा 30.05.2018 को अनुसमर्थन किया गया था।

दण्डादेशित व्यक्तियों के स्थानान्तरण के संबंध में भारत की सरकार और किंगडम ऑफ स्पेन के बीच करार

इसके उपरान्त भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ स्पेन को संविदाकारी देश कहा जाएगा;

दण्डादेशित व्यक्तियों के अपने-अपने देश में सामाजिक पुनर्वास को सुलभ बनाने की वांछा करते हुए; और

यह विचार करते हुए कि विदेशी नागरिकों, जिन्हें कोई अपराध कारित करने के परिणामस्वरूप अभियोजित किया गया है और सज़ा प्रदान की गई है, को उनके अपने समाज में सज़ा काटने का अवसर देकर यह उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

करार के प्रयोजन के लिए:

- (क) “अधिनिर्णय” का अर्थ है कि न्यायालय या न्याधिकरण का निर्णय या आदेश जो सज़ा देता है;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” का अर्थ ऐसा वह देश जिसमें दण्डादेशित व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए या बाकी बची सज़ा काटने के लिए स्थानांतरित किया जा सके या स्थानांतरित किया गया है;

- (ग) “सज़ा” का अर्थ है ऐसी सज़ा दंड या उपाय जिसमें आपराधिक न्यायाधिकार के प्रयोग हेतु न्यायालय या न्याधिकरण द्वारा आदेशित स्वतंत्रता से वंचित रखना शामिल हो;
- (घ) “सज़ाप्राप्त व्यक्ति” का अर्थ है वह व्यक्ति जो आपराधिक न्यायालय द्वारा, जिसमें संविदाकारी देशों में लागू कानून के अंतर्गत उस समय के लिए गठित न्यायालय शामिल हैं, दिए गए अधिनिर्णय के अंतर्गत कारावास की सज़ा काट रहा हो;
- (ङ.) “स्थानान्तरणकर्ता देश” का अर्थ है वह देश जिसमें उस व्यक्ति को सज़ा दी गई थी, और जिसको स्थानान्तरित किया जा सकता है या किया गया है।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धान्त

1. किसी एक संविदाकारी देश के क्षेत्र में दण्डादेशित व्यक्ति को इस करार के प्रावधानों के अनुसार उसे मिली सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकारी देश के क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ, वह स्थानान्तरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश को इस करार के अंतर्गत स्थानान्तरित होने के लिए अपनी इच्छा के बारे में बता सकता है।
2. किसी भी दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जो संविदाकारी देश का नागरिक हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जा सकता है जो संविदाकारी देश को आवेदन प्रस्तुत करके संविदाकारी देश के कानून के निर्धारित तरीके से, उनकी ओर से कार्य करने का हकदार हो।

अनुच्छेद 3

केन्द्रीय प्राधिकरण

1. संविदाकारी देशों की ओर से इस करार के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी प्राधिकरण निम्नानुसार है:

(क) भारत गणराज्य की ओर से : गृह मंत्रालय

(ख) किंगडम ऑफ स्पेन की ओर से : न्याय मंत्रालय
2. यदि संविदाकारी देशों में से कोई अपने सक्षम प्राधिकरणों को बदलता है, वह दूसरे देश को इस बारे में राजनयिक माध्यम से अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 4

स्थानान्तरण के लिए शर्तें

1. दण्डादेशित व्यक्ति को इस करार के अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियों में स्थानान्तरित किया जा सकता है:

(क) व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक है;

(ख) दंडादेशित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया है सिवाय उस मामले में जहां सज़ा को कम किया गया हो;

(ग) अधिनिर्णय अंतिम है;

(घ) स्थानान्तरित करने वाले देश में दंडादेशित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई लम्बित नहीं है जिसमें उनकी, उपस्थिति अपेक्षित है;

(ङ.) दण्डादेशित व्यक्ति को मिलिटरी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है सिवाय उन परिस्थितियों में जहां संविदाकारी देश अन्यथा सहमत हों;

(च) स्थानान्तरण के लिए किए गए अनुरोध की प्राप्ति के समय सज़ा प्राप्त व्यक्ति को एक वर्ष की सज़ा काटना बाकी है।

(छ) वे कृत्य या अपराध जिनके लिए उस व्यक्ति को स्थानान्तरणकर्ता देश में सज़ा प्रदान की गई थी, वो प्राप्तकर्ता देश में अपराध के रूप में दण्डनीय है, या अपराधिक अपराध कहलाते हैं यदि ये उनके क्षेत्र में कारित किए जाते हैं;

(ज) दंडादेशित व्यक्ति की अभिरक्षा प्राप्तकर्ता देश में अंतरित करना, स्थानान्तरणकर्ता देश की प्रभुता, सुरक्षा या किसी अन्य आवश्यक हित के विरुद्ध नहीं होगी;

(झ) दंडादेशित व्यक्ति द्वारा स्थानान्तरण के लिए सहमति दी जाती है, या उसकी आयु या शारीरिक या मानसिक स्थिति के मद्देनजर कोई संविदाकारी देश यह आवश्यक समझता है कि संविदाकारी देश के कानून के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से कार्य करने का हकदार होगा; और

(ञ) स्थानान्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश स्थानान्तरण के लिए सहमत हों।

2. अपवादिक मामलों में, स्थानान्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश दण्डादेशित व्यक्ति द्वारा शेष भुगते जाने वाली अवधि पैराग्राफ 1 च में उल्लिखित अवधि से कम होने पर भी स्थानान्तरण हेतु सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 5

सूचना प्रदान करने संबंधी दायित्व

1. यदि दण्डादेशित व्यक्ति ने स्थानान्तरण देश से इस करार के अन्तर्गत स्थानान्तरित होने की रूचि अभिव्यक्त की है, तब स्थानान्तरणकर्ता देश, जब तक यदि प्राप्तकर्ता और स्थानान्तरणकर्ता देश में से कोई भी देश यह पहले ही निर्णय नहीं कर चुका है कि वह स्थानान्तरण के लिए सहमत नहीं होगा, प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा:

(क) प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म की तारीख और स्थान और पता, यदि कोई हो, साथ ही उसके पासपोर्ट अथवा किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज की एक प्रति, और यथासम्भव दण्डादेशित व्यक्ति की उंगलियों के निशान भी भेजेगा।

(ख) उन तथ्यों की विवरणी जिन पर सज़ा देना आधारित था;

(ग) सज़ा की प्रकृति, अवधि और आरम्भ होने की तारीख, एक विवरणी जिसमें कि विचारण-पूर्व कैद, माफी दण्ड के प्रवर्तन के संगत कोई अन्य तथ्य सहित कितनी सज़ा पहले ही काटी जा चुकी है, को दर्शाया गया हो; तथा

(घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति और कानून के उस संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अन्तर्गत दण्डादेशित व्यक्ति को सज़ा प्रदान की गई है।

(ङ.) जब भी उपयुक्त हो, दण्डादेशित व्यक्ति के बारे में चिकित्सा, सामाजिक अथवा सुधार-गृह की रिपोर्ट, दण्डादेश देने वाले राज्य में उसके इलाज के बारे में सूचना, और सम्बन्धित राज्य में उसके और आगे इलाज के लिए कोई सिफारिश;

(च) कोई अन्य सूचना जिसे प्राप्तकर्ता देश, उसे स्थानान्तरण की संभावना पर विचार करने के लिए अधिकार देने और उसे उसके कानून के अधीन दण्डादेशित व्यक्ति को स्थानान्तरण के पूरे परिणामों के बारे में सूचित करने का अधिकार देने के लिए, आवश्यक होना विनिर्दिष्ट करे।

(छ) स्थानान्तरित किए जाने वाले दण्डादेशित व्यक्ति का अनुरोध अथवा स्थानान्तरणकर्ता देश की विधि के अनुसार उसकी तरफ से कार्रवाई करने के लिए हकदार व्यक्ति का अनुरोध; तथा

(i) स्थानान्तरणकर्ता देश से दण्डादेशित व्यक्ति के स्थानान्तरण पर सहमति संबंधी एक विवरणी।

2. इस करार के अन्तर्गत अनुरोध के बारे में कोई निर्णय लेने का अधिकार देने के उद्देश्य से, प्राप्तकर्ता देश, जब तक यदि प्राप्तकर्ता और स्थानान्तरणकर्ता देश में कोई भी देश यह पहले ही निर्णय नहीं कर चुका है कि वह स्थानान्तरण के लिए सहमत नहीं होगा, स्थानान्तरणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा:

(क) विवरणी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दण्डादेशित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है।

(ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान है कि वह क्रिया कलाप अथवा अनाचरण जिसके कारण स्थानान्तरणकर्ता देश में दण्ड आरोपित किया गया है, जो प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध गठित करता है, अथवा उसके भू-भाग में कारित किए जाने पर दण्डनीय अपराध माना जाएगा;

(ग) यदि लागू हो तो, दण्डादेशित व्यक्ति संबंधी इस करार के अनुच्छेद 9 के पैरा 2 के प्रभाव संबंधी विवरणी सहित दण्डादेशित व्यक्ति के स्थानान्तरण के पश्चात् प्राप्तकर्ता देश में सज़ा की अवधि और इसके प्रवर्तन के संबंध में किसी कानून या विनियम के प्रभाव की विवरणी;

- (घ) दण्डादेशित व्यक्ति के स्थानान्तरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सम्मति और दण्डादेशित व्यक्ति की बाकी बची सज़ा पूरी कराने के लिए एक वचनपत्र; तथा
- (ङ.) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे स्थानान्तरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 6

अनुरोध और उत्तर

1. स्थानान्तरण हेतु अनुरोध, लिखित में किए जाएंगे और स्थानान्तरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राजनयिक माध्यमों से प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित किए जाएंगे। उत्तर भी उन्हीं माध्यमों से भेजे जाएंगे।
2. प्राप्तकर्ता देश अपने इस निर्णय के बारे में, सहमत हुआ जाए या नहीं, स्थानान्तरणकर्ता देश को शीघ्र सूचित करेगा।

अनुच्छेद 7

सम्मति और इसका सत्यापन

1. स्थानान्तरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1(i) के अनुसार, स्थानान्तरण की अपेक्षित सम्मति देने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा स्वेच्छा से और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। ऐसी सम्मति देने की प्रक्रिया, स्थानान्तरणकर्ता देश कानून द्वारा शासित होगी।
2. स्थानान्तरणकर्ता देश, यह सत्यापित करने के लिए कि ऐसी सम्मति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है, प्राप्तकर्ता देश को एक अवसर प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 8

प्राप्तकर्ता देश पर स्थानान्तरण का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन, उसके राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सज़ा का प्रवर्तन जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के उपबंधों के शर्ताधीन, सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगा और केवल वही देश सभी समुचित निर्णय लेने में सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9

सज़ा का लगातार प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश, स्थानान्तरणकर्ता देश द्वारा यथानिर्धारित सज़ा की विधिक प्रवृत्ति और अवधि के लिए बाध्य होगा।
2. सज़ा यदि इसकी प्रकृति और अवधि, अथवा दोनों, के हिसाब से प्राप्तकर्ता देश के कानून के संगत नहीं है, तो वह देश, स्थानान्तरणकर्ता देश की पूर्व सम्मति से न्यायालय के या प्रशासनिक आदेश द्वारा उसी प्रकार के अपराध हेतु, अपने राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, उसके स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सज़ा के अनुसार सज़ा को रूपान्तरित कर सकता है। सज़ा की प्रकृति और अवधि से संबंधित रूपान्तरित सज़ा, जहां तक संभव हो, स्थानान्तरणकर्ता देश के निर्णय द्वारा आरोपित सज़ा के समान होगी। यद्यपि, यह स्थानान्तरणकर्ता देश द्वारा दी गई सज़ा को अपनी प्रकृति या अवधि द्वारा बढ़ाई नहीं जाएगी।

अनुच्छेद 10

स्थानान्तरणकर्ता देश पर सज़ा पूरी करने का प्रभाव

प्राप्तकर्ता देश जब इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1(क) के अन्तर्गत स्थानान्तरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि सज़ा पूरी हो गई है, तब ऐसी अधिसूचना स्थानान्तरणकर्ता देश में सज़ा पूरी करने के प्रभाव के रूप में मानी जाएगी।

अनुच्छेद 11

निर्णय और क्षमादान, राजक्षमा, अथवा लघुकरण की पुनरीक्षा

1. केवल स्थानान्तरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा हेतु किसी आवेदन के बारे में निर्णय करेगा।
2. संविदाकारी देशों में से कोई भी देश अपने संविधान और अन्य कानूनों के अनुसार क्षमादान, राजक्षमा अथवा सज़ा का लघुकरण कर सकता है और वह ऐसे निर्णय के बारे में दूसरे संविदाकारी देश को अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 12**सज़ा प्रवर्तन का समापन**

1. स्थानान्तरणकर्ता देश उसके भू-भाग पर लिए गए उन किन्हीं भी निर्णयों के बारे में जिनसे सज़ा अथवा सज़ा के किसी भाग के प्रवर्तन का समापन होता हो, अविलम्ब प्राप्तकर्ता देश को अधिसूचित करेगा।
2. स्थानान्तरणकर्ता देश द्वारा किसी निर्णय अथवा ऐसे किसी उपाय, जिसके परिणामस्वरूप सज़ा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, के बारे में जैसे ही सूचित किया जाता है, प्राप्तकर्ता देश सज़ा अथवा इसके किसी हिस्से के प्रवर्तन का समापन कर देगा।

अनुच्छेद 13**सज़ा प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश स्थानान्तरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:
 - (क) जब सज़ा प्रवर्तन पूरा किया जा चुका है; अथवा
 - (ख) यदि दण्डादेशित व्यक्ति सज़ा प्रवर्तन पूरा हो जाने से पहले ही हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश उसकी शेष सज़ा पूरी कराने के प्रयोजनों हेतु उसे हिरासत में लिए जाने तथा प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत अपराध कारित करने हेतु उसे उत्तरदायी घोषित करने हेतु उपाय करेगा।
2. यदि स्थानान्तरणकर्ता देश ऐसी अपेक्षा करता है तो प्राप्तकर्ता देश सज़ा के प्रवर्तन के संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 14**पारगमन**

1. यदि कोई भी संविदाकारी देश किसी अन्य तीसरे देश के साथ दण्डादेशित व्यक्तियों के स्थानान्तरण हेतु समझौते करता है, तो दूसरा संविदाकारी देश ऐसे समझौतों के अनुसरण में स्थानान्तरित किए जा रहे दण्डादेशित व्यक्तियों का अपने भू-भाग से पारगमन सुलभ करने हेतु सहयोग करेगा, यह देश पारगमन से केवल तब इंकार कर सकता है:
 - (क) यदि दण्डादेशित व्यक्ति उसके स्वयं के नागरिकों में से एक है।
 - (ख) यदि अनुरोध से संविदाकारी देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा अन्य किसी आवश्यक हित का अतिक्रमण होता है।
2. ऐसा स्थानान्तरण चाहने वाला संविदाकारी देश ऐसे पारगमन के बारे में दूसरे संविदाकारी देश को अग्रिम सूचना देगा।

अनुच्छेद 15**लागत**

इस करार की प्रयुक्ति पर किए जाने वाली लागतों का वहन प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाएगा सिवाय उन लागतों के जो केवल स्थानान्तरणकर्ता देश के भू-भाग में होती हैं।

अनुच्छेद 16**भाषा**

अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अनुरोध और समर्थक दस्तावेज, जब प्राप्तकर्ता देश स्पेन हो तो स्पेनिश में अनुवाद और जब प्राप्तकर्ता देश भारत हो तो अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न किया जाएगा।

अनुच्छेद 17**प्रयुक्ति का क्षेत्र**

यह करार, इस करार के लागू होने से पहले अथवा इसके पश्चात् प्रदान किए गए दंडादेशों के प्रवर्तन के संबंध में लागू होगा।

अनुच्छेद 18**विवादों का निपटारा**

1. केन्द्रीय प्राधिकरण इस करार के निर्वचन, लागू होने अथवा इसके कार्यान्वयन से व्युत्पन्न किसी विवाद को पारस्परिक रूप से निपटाने का प्रयास करेंगे।
2. यदि केन्द्रीय प्राधिकरण किसी विवाद को आपस में नहीं सुलझा पाते हैं तो इसे राजनयिक माध्यमों से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 19**दण्डादेशित व्यक्तियों की सुपुर्दगी**

स्थानान्तरणकर्ता देश द्वारा स्थानान्तरित व्यक्ति की प्राप्तकर्ता देश को सुपुर्दगी स्थानान्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश के मध्य मतैक्य वाले स्थान पर की जाएगी। प्राप्तकर्ता देश बंदी के स्थानान्तरणकर्ता देश से अभिगमन हेतु उत्तरदायी होगा और स्थानान्तरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दण्डादेशित व्यक्ति की हिरासत के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 20**संशोधन**

संविदाकारी देशों द्वारा इस करार में किसी संशोधन अथवा आशोधन पर बनी सहमति इस करार के प्रवृत्त होने के तरीके से ही प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 21**अन्तिम प्रावधान**

1. यह करार, संविदाकारी देशों द्वारा इस करार के प्रवृत्त होने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के पश्चात् एक दूसरे को लिखित में अधिसूचित करने की तारीख के तीस दिन के बाद लागू होगा।
2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि, कोई भी संविदाकारी देश इस करार को, दूसरे संविदाकारी देश को इस करार को समाप्त करने की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है। यह समापन ऐसे नोटिस की तारीख से छह माह के बाद प्रभावी होगा।
3. समापन के बावजूद, यह करार उन बंदियों की सजा के प्रवर्तन पर लागू होता जारी रहेगा जिन्हें इस करार के अधीन इस करार के समाप्त होने की तारीख से पहले स्थानान्तरित किया गया है।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होने पर, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वर्ष 2017 की 30वीं तारीख को मई में मैड्रिड में हिन्दी, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियां में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। तथापि, निर्वचन की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार**की ओर से****किंगडम ऑफ स्पेन****की ओर से**

नाम : श्री डी.बी. वेंकटेश वर्मा

पदनाम : भारतीय राजदूत, मैड्रिड

नाम : श्री राफेल काटाला पोलो

पदनाम : न्याय मंत्री, स्पेन सरकार

[फा. सं. V-17011/12/2012-पीआर]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Women Safety Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2018

G.S.R. 1140E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Kingdom of Spain. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed between the Republic of India and the Kingdom of Spain on 30.5.2017 is given below. The Agreement was ratified by the Government of the Republic of India on 3.7.2017 and by the Government of the Kingdom of Spain on 30.5.2018.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF SPAIN ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Spain hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2

General Principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

ARTICLE 3

Central Authorities

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
 - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
 - For the Kingdom of Spain: Ministry of Justice
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

ARTICLE 4

Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the receiving State;

- (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person; except the case where the sentence has been commuted;
- (c) the judgment is final;
- (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required;
- (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law except in circumstances where the Contracting States agree otherwise;
- (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve;
- (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be detrimental to the sovereignty, security or any other essential interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than specified in paragraph 1(f).

ARTICLE 5

Obligation to furnish information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the Sentenced Person, as possible;
- (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence, a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement;
- (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (e) Whenever appropriate, any medical, social or penitentiary report on the sentenced person, information about his treatment in the sentencing State, any recommendation for his further treatment in the administering State,;
- (f) any other information which the receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
- (h) A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the transferring State constitute a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement regarding any law regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

ARTICLE 6

Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing and addressed by the Central authority of the transferring State through diplomatic channels to the Central Authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 7

Consent and its verification

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8

Effect of transfer for the receiving State

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 9

Continued enforcement of sentence

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.

2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the receiving State, that State may, with the prior consent of the transferring State, by court or administrative order, as may be required under its national law, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar

offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the transferring State.

ARTICLE 10

Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring state under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the transferring state.

ARTICLE 11

Review of judgment and Pardon, amnesty or commutation

1. The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws and shall notify the other Contracting State of such decision.

ARTICLE 12

Termination of enforcement of sentence

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13

Information on enforcement of sentence

1. The receiving State shall notify the transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/ her liable for committing an offence under the relevant law of the receiving State.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 14

Transit

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit;
 - (a) if the sentenced person is one of its own nationals;
 - (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15**Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State.

ARTICLE 16**Language**

Requests and supporting documents under Article 5 shall be accompanied by a Spanish translation when Spain is the receiving State and into English when India is the receiving State.

ARTICLE 17**Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18**Settlement of Disputes**

- (1) The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 19**Handing Over of Sentenced Persons**

The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

ARTICLE 20**Amendments**

Any amendment or modification to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

ARTICLE 21**Final Provisions**

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting States have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with.
2. The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Madrid on the 30th day of May 2017, in the Hindi, English and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail

For the Government of
The Republic of India

Name : D. B. Venkatesh Varma
Designation: Ambassador of India, Madrid

For the Government of
The Kingdom of Spain

Name: Rafael Catala Polo
Designation: Minister of Justice,
Government of Spain.

[F. No. V-17011/12/2012-PR]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.